



न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-123/2018

बउनवान

भैरूलाल उम्र 73 वर्ष पुत्र चम्पालाल जाति कुमावत निवासी किशनपुरा मसालदारान तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारां

(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री ललित कुमार नागर अभिभाषक
2- पेरोंकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 15.05.2019

अपीलांट ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 81/2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम किशनपुरा मसालदारान की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2073 में खसरा नम्बर 170/558 की रकबा 0.30 हेक्टर भूमि पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 31.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये, पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय साईक्लो स्टाईल परफॉर्मा पर पारित किया है जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट काफी वृद्ध है उसका उक्त आराजियात पर कभी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आसपास के खेत वालों से कोई तहकीकात नहीं की तथा अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.02.18 को पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद

दिनांक 23.02.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 20.03.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको न्यायालय के प्रकरण संख्या 466/16 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 पर दिये गये आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2073 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। पत्रावली में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 81/2017 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि नायब तहसीलदार कवाई फसल बुवाई के समय माह जुलाई एवं अगस्त 2019 में 2 बार जाँच करे, कि अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम किशनपुरा मसालदारान तहसील अटरू के खसरा नम्बर 170/558 की रकबा 0.30 हेक्टर भूमि किस्म चारागाह से कब्जा छोड़ दे, तो नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 81/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 27.02.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर,
बारां